शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-4.0
Vol.-3; issue-2 (April-June) 2026
Page No- 228-239
©2026 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. चंद्रशेखर प्रसाद

अतिथि सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, महारानी जानकी कुंवर कॉलेज, बेतिया, अंगीभूत इकाई, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर (बिहार).

Corresponding Author :

डॉ. चंद्रशेखर प्रसाद

अतिथि सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, महारानी जानकी कुंवर कॉलेज, बेतिया, अंगीभूत इकाई, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर (बिहार).

महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स : आधुनिक सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति दृष्टिकोणों का एक तुलनात्मक अध्ययन

सारांश : यह शोध पत्र आधुनिक युग के दो महानतम विचारकों, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यद्यपि दोनों विचारकों का अंतिम लक्ष्य एक समान था—एक ऐसे वर्गविहीन, शोषणमुक्त और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना जहाँ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण हो—किंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग और साधन पूरी तरह भिन्न थे।

जहाँ कार्ल मार्क्स का दर्शन 'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद', 'वर्ग-संघर्ष' और 'सशस्त्र क्रांति' पर आधारित है, जो पूंजीवाद को समूल नष्ट कर उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार स्थापित करना चाहता है; वहीं महात्मा गांधी का दृष्टिकोण नैतिक, आध्यात्मिक और 'अहिंसा', 'सर्वोदय' (सबका उदय) तथा 'ट्रस्टीशिप' (न्यासधारिता) के सिद्धांतों पर टिका है। गांधी जी हृदय-परिवर्तन और आर्थिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए दोनों के वैचारिक अंतर्विरोधों और समानताओं को रेखांकित करता है। निष्कर्षतः, यह पत्र यह दर्शाता है कि 21वीं सदी की बढ़ती आर्थिक असमानता और कॉर्पोरेट पूंजीवाद के दौर में, जहाँ मार्क्स का आर्थिक विश्लेषण प्रासंगिक है, वहीं सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए गांधी का अहिंसक और मानवीय मार्ग अधिक टिकाऊ और व्यावहारिक प्रतीत होता है।

मुख्य शब्द : सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, वर्ग-संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक-आर्थिक न्याय, अहिंसा, साम्यवाद।

प्रस्तावना : उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी का इतिहास मानव सभ्यता के वैचारिक और संरचनात्मक रूपांतरण का काल रहा है। औद्योगिक क्रांति ने जहाँ एक ओर उत्पादन के साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर इसने समाज को दो प्रतिरोधी ध्रुवों में विभाजित कर दिया। इस संक्रमण काल ने पारंपरिक सामंती व्यवस्था को विस्थापित कर आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीवाद के इस अनियंत्रित विकास ने संपत्ति के संकेंद्रण और मानवीय श्रम के शोषण की तीव्र प्रक्रिया शुरू

की, जिसने तात्कालिक बुद्धिजीवियों को सामाजिक-आर्थिक न्याय के नए प्रतिमान खोजने पर विवश किया (Polanyi, 1944)।

इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वैश्विक पटल पर दो महान वैचारिक धाराओं का उदय हुआ, जिनके प्रणेता कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी थे। मार्क्स ने यूरोप के औद्योगिक पूंजीवाद की क्रूर विसंगतियों को अत्यंत निकट से देखा और अपनी कालजयी कृति *'दास कैपिटल'* (1867) में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का वैज्ञानिक और भौतिकवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया। मार्क्स का मानना था कि इतिहास की समस्त गतिकी आर्थिक संबंधों और वर्ग-संघर्षों से संचालित होती है (Marx & Engels, 1848)। दूसरी ओर, बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक भारत की पृष्ठभूमि में पूंजीवाद और पश्चिमी औद्योगिकीकरण की यांत्रिक क्रूरता को चुनौती दी। गांधी जी ने अपनी मौलिक पुस्तक *'हिंद स्वराज'* (1909) में स्पष्ट किया कि आधुनिक सभ्यता का संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे रूप में नैतिक और आध्यात्मिक है। इस प्रकार, जहाँ मार्क्स पश्चिमी औद्योगिक समाज की संरचनात्मक हिंसा के विरुद्ध एक वैज्ञानिक विकल्प लेकर आए, वहीं गांधी एशियाई महाद्वीप में औपनिवेशिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक नैतिक और विकेंद्रीकृत प्रतिमान लेकर खड़े हुए।

समस्या का परिचय : समकालीन विश्व समतामूलक समाज के दावों के बावजूद एक गहरे सामाजिक-आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण और नव-उदारवादी (Neo-liberal) नीतियों ने आर्थिक असमानता को उस स्तर पर पहुँचा दिया है जहाँ न्याय की अवधारणा केवल अकादमिक बहसों तक सीमित रह गई है। ऑक्सफैम (Oxfam) की नवीनतम रिपोर्ट 'इन्इक्वालिटी किल्स' (2022) और वैश्विक आर्थिक मंचों के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि दुनिया की अधिकांश संपत्ति पर मात्र एक प्रतिशत कॉरपोरेट कुलीन वर्ग का नियंत्रण है, जबकि बहुसंख्यक आबादी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रही है (Oxfam, 2022; Piketty, 2014)।

समस्या केवल धन की असमानता की नहीं है, बल्कि उस तंत्र की है जो इस असमानता को वैधता प्रदान करता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखें तो आज भी 'अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत' (Theory of Surplus Value) नए डिजिटल और कॉरपोरेट रूपों में जीवित है, जहाँ श्रमिक का अपने श्रम से अलगाव (Alienation) बढ़ता जा रहा है (Marx, 1959)। वहीं, गांधीवादी दृष्टिकोण से समस्या यह है कि आधुनिक समाज ने साध्य (आर्थिक विकास) की अंधी दौड़ में साधनों (नैतिकता, मानवीय मूल्य और अहिंसा) की पवित्रता को पूरी तरह भुला दिया है (Gandhi, 1927)। संक्षेप में, समस्या का केंद्रीय बिंदु यह है: *"क्या आधुनिक पूंजीवाद जनित इस भयानक सामाजिक-आर्थिक असमानता का समाधान मार्क्स के क्रांतिकारी भौतिकवाद और वर्ग-उन्मूलन में निहित है, या फिर गांधी के नैतिक हृदय-परिवर्तन, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में?"* इन दोनों उपागमों (Approaches) के अंतर्विरोध और उनकी सीमाओं का तार्किक विश्लेषण ही इस शोध की मुख्य समस्या है।

शोध का महत्व : इस शोध का महत्व समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्शों में अत्यंत गहरा है। वर्तमान 21वीं सदी में जब राज्य अपनी कल्याणकारी (Welfare State) भूमिका से पीछे हट रहा है और बाजारवादी ताकतें हावी हो रही हैं, तब न्याय की पुनर्परिभाषा आवश्यक हो गई है। यह शोध पत्र पारंपरिक दृष्टिकोणों से आगे बढ़कर गांधी और मार्क्स के दर्शन को एक नए और एकीकृत फलक पर देखता है।

अकादमिक रूप से, यह शोध इस भ्रांति को तोड़ता है कि गांधी और मार्क्स एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं। प्रख्यात समाजवादी विचारक डॉ. राममनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक *'मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म'* (1963) में तर्क दिया था कि आधुनिक समाजवाद को यदि जीवित रहना है, तो उसे मार्क्स के अर्थशास्त्र और गांधी की नैतिकता के बीच एक पुल का निर्माण करना होगा (Lohia, 1963)। यह शोध इसी पुल की वर्तमान प्रासंगिकता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में गांधी का 'सीमित उपभोग' (Minimalism) का विचार और मार्क्स का 'प्रकृति और मनुष्य के बीच चयापचय दरार' (Metabolic Rift) का सिद्धांत मिलकर सतत विकास (Sustainable Development) का एक नया मॉडल प्रस्तुत करते हैं (Foster, 1999)। इसलिए, यह शोध नीति-निर्माताओं, समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के लिए एक ऐसा

वैचारिक हाइब्रिड मॉडल (Hybrid Model) सुझाने में महत्वपूर्ण है जो समतामूलक भी हो और मानवीय भी।

शोध के उद्देश्य : प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **उद्देश्य 1:** महात्मा गांधी के 'सर्वोदय', 'अहिंसा' और 'ट्रस्टीशिप' (न्यासधारिता) के सिद्धांतों के आलोक में उनके सामाजिक-आर्थिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण का विस्तृत विश्लेषण करना।
- **उधेश्य 2:** कार्ल मार्क्स के 'ऐतिहासिक भौतिकवाद', 'वर्ग-संघर्ष' और 'सर्वहारा की तानाशाही' के सिद्धांतों के माध्यम से उनके क्रांतिकारी न्याय प्रतिमान का आलोचनात्मक परीक्षण करना।
- **उद्देश्य 3:** दोनों विचारकों के दर्शन में विद्यमान वैचारिक समानताओं (जैसे शोषण का विरोध, वर्गविहीन/राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य) और बुनियादी असमानताओं (जैसे साधन बनाम साध्य, भौतिकवाद बनाम आध्यात्मिकता) का तुलनात्मक मूल्यांकन करना।
- **उद्देश्य 4:** 21वीं सदी के वैश्वीकरण, कॉरपोरेट पूंजीवाद और बढ़ती आर्थिक असमानता के दौर में दोनों दर्शनों की समकालीन प्रासंगिकता और व्यावहारिकता को रेखांकित करना।

महात्मा गांधी का दृष्टिकोण: नैतिक और विकेंद्रीकृत न्याय : महात्मा गांधी का सामाजिक-आर्थिक दर्शन किसी पारंपरिक पश्चिमी अर्थशास्त्री की तरह विशुद्ध गणितीय आंकड़ों या भौतिकवादी नियमों पर आधारित नहीं था। उनका दृष्टिकोण मूलतः नैतिक, आध्यात्मिक और मानवतावादी था। गांधी जी का मानना था कि अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र (Ethics) को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था:

"वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, वह मोम के पुतले की तरह है जो देखने में तो सजीव लगता है, लेकिन जैसे ही वह जीवन की गर्मी के संपर्क में आता है, पिघल कर नष्ट हो जाता है।" (Gandhi, 1921)

गांधी जी के सामाजिक-आर्थिक न्याय के इस प्रतिमान को समझने के लिए इसे चार मुख्य स्तंभों के अंतर्गत विश्लेषित किया जा सकता है:

1. गांधीवादी आर्थिक न्याय के मूल स्तंभ : गांधी जी के आर्थिक न्याय की पूरी संरचना चार प्रमुख सिद्धांतों पर टिकी हुई है, जिसे नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। यह संरचना पूंजीवाद और राज्य-नियंत्रित साम्यवाद दोनों का एक अनूठा नैतिक विकल्प प्रस्तुत करती है:

2. सर्वोदय: समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान : गांधी जी का 'सर्वोदय' का सिद्धांत जॉन रस्किन की पुस्तक *'अनटू दिस लास्ट'* (Unto This Last) से प्रेरित था, जिसका अर्थ है—"सबका उदय" या "सबका कल्याण" (Gandhi, 1927)। यह पश्चिमी लोकतंत्र के 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' (Utilitarianism) के सिद्धांत का खंडन करता है, क्योंकि उपयोगितावाद में बहुसंख्यक के सुख के लिए अल्पसंख्यक के हितों की बलि दी जा सकती है।

गांधी जी का सर्वोदय यह मांग करता है कि न्याय की शुरुआत समाज के सबसे कमजोर, गरीब और हाशिए पर मौजूद व्यक्ति (जिसे उन्होंने 'दरिद्रनारायण' कहा) से होनी चाहिए। उनके प्रसिद्ध 'जंतर' (Talisman) में

भी यही सामाजिक न्याय परिलक्षित होता है, जहाँ वे कहते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोचो कि उससे समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को क्या लाभ पहुँचेगा।

3. ट्रस्टीशिप (न्यासधारिता) का सिद्धांत : पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बीच की वैचारिक खाई को पाटने के लिए गांधी जी ने 'ट्रस्टीशिप' का एक अनूठा और अहिंसक सिद्धांत प्रस्तुत किया। मार्क्स जहाँ पूंजीपतियों के हिंसक सफाए और संपत्ति के जबरन राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, वहीं गांधी जी 'हृदय-परिवर्तन' (Change of Heart) पर विश्वास करते थे।

- **मूल अवधारणा:** ट्रस्टीशिप के तहत अमीर व्यक्तियों को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक की संपत्ति का वास्तविक मालिक नहीं, बल्कि समाज की ओर से उसका **'न्यासी' (Trustee)** या संरक्षक मानना चाहिए।
- **अहिंसक समाजवाद:** गांधी जी के अनुसार, *"पूंजीपतियों के पास जो धन है, वह समाज के श्रम का परिणाम है। इसलिए, उस धन पर पहला हक समाज का है।"* (Gandhi, 1940)। यदि कोई अमीर अपनी स्वेच्छा से ट्रस्टी बनना स्वीकार नहीं करता, तब गांधी जी ने उसके विरुद्ध अहिंसक असहयोग और सत्याग्रह का मार्ग सुझाया, ताकि व्यवस्था को नैतिक रूप से झुकाया जा सके।

4. आर्थिक विकेंद्रीकरण और खादी दर्शन : गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि बड़े पैमाने पर होने वाला औद्योगिकीकरण (Industrialization) अनिवार्य रूप से शोषण, बेरोजगारी और शहरों की ओर पलायन को जन्म देता है। इसलिए उन्होंने बड़े उद्योगों के स्थान पर 'कुटीर उद्योगों' (Cottage Industries) और 'श्रम-प्रधान अर्थव्यवस्था' की वकालत की।

साधन और साध्य: दोनों मॉडलों के परिणामों का तुलनात्मक प्रदर्शन

- **उत्पादन का विकेंद्रीकरण:** गांधी जी 'सामूहिक उत्पादन' (Mass Production) के विरोधी थे, वे **'जनता द्वारा उत्पादन' (Production by Masses)** के समर्थक थे। उनका खादी और चरखे का दर्शन केवल वस्त्र बनाने का साधन नहीं था, बल्कि वह आर्थिक आत्मनिर्भरता और विदेशी आर्थिक दासता से मुक्ति का प्रतीक था।
- **मशीनों पर दृष्टिकोण:** गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे मशीनों के उस पागलपन के विरोधी थे जो इंसानों को बेकार कर देता है। वे ऐसी तकनीक चाहते थे जो मानव के हाथ को काम दे, न कि उसका काम छीन ले।

5. साध्य और साधन की पवित्रता (Means and Ends) : गांधीवादी न्यायशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि न्यायपूर्ण साध्य (Just Ends) की प्राप्ति केवल न्यायपूर्ण साधनों (Just Means) से ही हो सकती है। गांधी जी का मानना था कि हिंसक साधनों से स्थापित किया गया कोई भी समाजवाद या न्याय कभी भी स्थाई नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा अपने साथ प्रतिशोध और दमन का एक नया चक्र शुरू करती है।

"साधन की तुलना बीज से और साध्य की तुलना पेड़ से की जा सकती है। जितना अपरिवर्तनीय संबंध बीज और पेड़ के बीच है, उतना ही साधनों और साध्य के बीच है।" (Gandhi, 1909)

इसलिए, गांधी जी वर्ग-संघर्ष के बजाय **'वर्ग-समन्वय' (Class Harmony)** पर बल देते हैं, जहाँ समाज का हर

वर्ग नैतिक रूप से जागृत होकर एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करता है।

कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण: भौतिकवादी और क्रांतिकारी न्याय : महात्मा गांधी के नैतिक और आध्यात्मिक उपागम के सर्वथा विपरीत, कार्ल मार्क्स का सामाजिक-आर्थिक न्याय का सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक, भौतिकवादी और क्रांतिकारी है। मार्क्स किसी भी प्रकार की धार्मिक नैतिकता, हृदय-परिवर्तन या पूंजीपतियों की परोपकारिता (जैसे ट्रस्टीशिप) को खारिज करते हैं। उनका मानना था कि विचार या नैतिकता समाज को नहीं बदलते, बल्कि समाज की आर्थिक संरचना (Economic Structure) हमारे विचारों और नैतिकता को तय करती है।

मार्क्स के सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रतिमान को समझने के लिए इसे निम्नलिखित प्रमुख दार्शनिक और आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत विश्लेषित किया जा सकता है:

1. मार्क्सवादी न्याय का आधार: ऐतिहासिक भौतिकवाद : कार्ल मार्क्स का दर्शन 'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद' (Dialectical Materialism) पर आधारित है। जब इसे इतिहास पर लागू किया जाता है, तो इसे 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' (Historical Materialism) कहा जाता है (Marx, 1859)।

- **अधोसंरचना बनाम अधिरचना:** मार्क्स के अनुसार, समाज की आर्थिक व्यवस्था ही उसकी 'अधोसंरचना' (Base/Understructure) होती है, जिसमें उत्पादन के साधन (भूमि, मशीनें, तकनीक) और उत्पादन के संबंध (मालिक और मजदूर) शामिल होते हैं।
- समाज की अन्य सभी व्यवस्थाएं—जैसे राजनीति, कानून, धर्म, संस्कृति और नैतिकता—इस आर्थिक आधार पर टिकी हुई 'अधिरचना' (Superstructure) मात्र हैं।

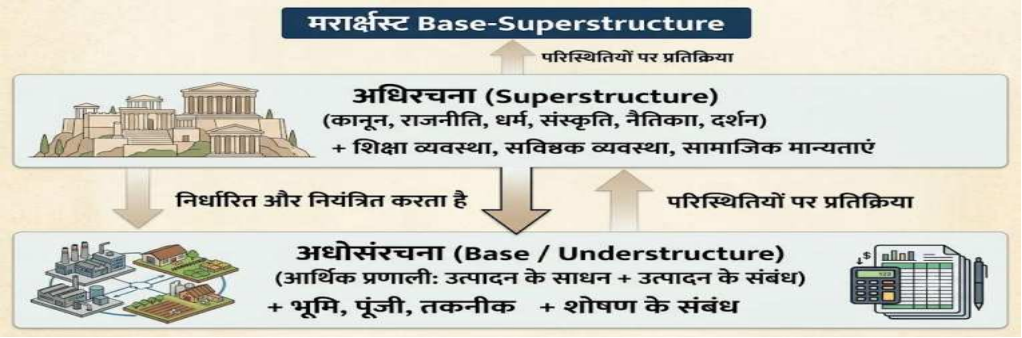

मार्क्स का तर्क है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का निजी नियंत्रण रहेगा, तब तक कानून और नैतिकता जैसी अधिरचनाएं भी केवल अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करेंगी और गरीबों का शोषण करती रहेंगी। इसलिए, वास्तविक आर्थिक न्याय नैतिक भाषणों से नहीं, बल्कि आर्थिक आधार (Base) को बदलने से ही संभव है।

2. वर्ग-संघर्ष (Class Struggle) और शोषण का सिद्धांत : मार्क्स और एंगेल्स ने *'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो'* (1848) की शुरुआत में ही यह घोषणा की थी: *"अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा है।" (Marx & Engels, 1848)*

मार्क्स के अनुसार, समाज हमेशा से दो विरोधी वर्गों में बंटा रहा है—एक वह जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है (शोषक/बुर्जुआ), और दूसरा वह जो केवल अपना श्रम बेचता है (शोषित/सर्वहारा)। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में यह खाई सबसे गहरी हो चुकी है।

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत (Theory of Surplus Value) : मार्क्स ने अपनी पुस्तक *'दास कैपिटल'* (1867) में वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि पूंजीवाद में न्याय क्यों असंभव है। उन्होंने **'अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत'** दिया:

- मजदूर दिनभर काम करके जो मूल्य पैदा करता है (मान लीजिए ₹1000) और उसे जो वास्तविक मजदूरी मिलती है (मान लीजिए ₹200), उन दोनों के बीच का अंतर (₹800) ही 'अतिरिक्त मूल्य' (Surplus Value) है।

- यह अतिरिक्त मूल्य पूरी तरह से मजदूर के पसीने की कमाई है, जिसे पूंजीपति 'लाभ' (Profit) के रूप में अपनी जेब में रख लेता है। मार्क्स इसी को पूंजीवादी शोषण और घोर अन्याय मानते हैं (Marx, 1867)।

3. श्रम से अलगाव (Alienation of Labour) : पूंजीवादी न्यायहीनता का एक और भयानक रूप 'अलगाव का सिद्धांत' है। मार्क्स की *'इकोनॉमिक एंड फिलॉसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स'* (1844) के अनुसार, पूंजीवादी व्यवस्था में अत्यधिक यंत्रीकरण और श्रम-विभाजन के कारण मजदूर चार स्तरों पर अलग-थलग (Alienated) हो जाता है (Marx, 1959):

मजदूर जिस वस्तु को बनाता है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। वह मशीन का एक बेजान पुर्जा बनकर रह जाता है, जिससे उसकी मानवीय रचनात्मकता नष्ट हो जाती है। मार्क्स के लिए सामाजिक न्याय का अर्थ इस अलगाव को समाप्त कर मनुष्य को उसकी वास्तविक मानवीय गरिमा लौटाना है।

4. क्रांतिकारी न्याय: सशस्त्र क्रांति और सर्वहारा की तानाशाही : मार्क्स का स्पष्ट मानना था कि शोषक वर्ग कभी भी स्वेच्छा से या शांतिपूर्ण तरीकों (जैसे हृदय-परिवर्तन) से अपनी संपत्ति और सत्ता नहीं छोड़ेगा। इसलिए, वे सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए **'सशस्त्र और हिंसक क्रांति' (Armed/Violent Revolution)** को अनिवार्य मानते हैं।

न्याय की स्थापना के चरणों को मार्क्स इस प्रकार रेखांकित करते हैं:

1. **सर्वहारा की क्रांति:** शोषित मजदूर संगठित होंगे और बलपूर्वक पूंजीवादी राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे।
2. **सर्वहारा की तानाशाही (Dictatorship of the Proletariat):** क्रांति के तुरंत बाद एक संक्रमणकालीन चरण आएगा, जहाँ राज्य की शक्ति का उपयोग पूंजीपतियों के बचे-खुचे अवशेषों को समाप्त करने और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए किया जाएगा।
3. **साम्यवाद (Communism):** अंततः एक ऐसा वर्गविहीन (Classless) और राज्यविहीन (Stateless) समाज स्थापित होगा, जहाँ निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन हो चुका होगा।

इस अंतिम साम्यवादी समाज में ही सच्चा सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित होगा, जिसका मूल मंत्र होगा:
"प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार।" *(From each according to his ability, to each according to his needs)* (Marx, 1875)

तुलनात्मक विश्लेषण: समानताएं और असमानताएं : महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स समकालीन वैश्विक इतिहास के दो ऐसे महान स्तंभ हैं, जिन्होंने समाज के सबसे पीड़ित और वंचित वर्ग के उद्धार को अपने जीवन का दर्शन बनाया। दोनों विचारकों का उद्गम स्थल, युगीन परिस्थितियाँ और दार्शनिक प्रवृत्तियाँ भिन्न थीं, जिसके कारण उनके मार्गों में गहरा अंतर्विरोध दिखाई देता है। तथापि, यदि उनके विचारों की अंतःसलिला को देखा जाए, तो दोनों के अंतिम उद्देश्य में एक अद्भुत साम्य भी नजर आता है।

प्रस्तुत अध्याय इन दोनों युगांतरकारी दार्शनिकों के दृष्टिकोणों का **अभिसरण (Convergence/समानताएं)** और **अपसरण (Divergence/असमानताएं)** के बिंदुओं के अंतर्गत एक

व्यापक और आलोचनात्मक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1. वैचारिक समानताएं (Points of Convergence) : गांधी और मार्क्स को सतही तौर पर एक-दूसरे का धुर विरोधी मान लिया जाता है, परंतु गंभीर अकादमिक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि दोनों के दर्शन में कई बुनियादी समानताएं मौजूद थीं। जैसा कि प्रसिद्ध गांधीवादी-समाजवादी विचारक आचार्य कृपलानी ने भी संकेत दिया था कि गांधी एक व्यावहारिक मार्क्सवादी थे जो हिंसा को छोड़कर मार्क्स के लक्ष्यों को स्वीकार करते थे। दोनों के बीच प्रमुख समानताएं निम्नलिखित हैं:

अ. वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य (The Ideal of a Stateless and Classless Society) : दोनों विचारकों का अंतिम राजनीतिक व सामाजिक आदर्श लगभग एक समान है। मार्क्स जहाँ पूंजीवाद की समाप्ति के बाद एक ऐसे **'साम्यवादी समाज' (Communism)** की कल्पना करते हैं जो वर्गविहीन (Classless) और राज्यविहीन (Stateless) होगा, वहीं गांधी जी भी **'रामराज्य' या 'पूर्ण स्वराज'** को एक ऐसे समाज के रूप में देखते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का वर्ग-भेद नहीं होगा और राज्य की दमनकारी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी (वह राज्य को 'संगठित हिंसा का प्रतीक' मानते थे)। दोनों ही मानते थे कि एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य (State) का स्वतः लोप या न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए (Gandhi, 1935; Marx, 1875)।

ब. पूंजीवाद और मानवीय शोषण का प्रखर विरोध (Critique of Capitalism) : दोनों ही चिंतक इस बात पर पूरी तरह सहमत थे कि पूंजीवादी व्यवस्था अनिवार्य रूप से बहुसंख्यक आबादी के शोषण पर टिकी हुई है। मार्क्स ने वैज्ञानिक रूप से दिखाया कि कैसे पूंजीपति श्रमिकों के 'अतिरिक्त मूल्य' का अपहरण करते हैं (Marx, 1867)। वहीं गांधी जी ने अपनी कृति *'हिंद स्वराज'* (1909) में पश्चिमी पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण को एक ऐसी 'शैतानी सभ्यता' कहा जो मनुष्य का वस्तुकरण करती है और उसे केवल धन कमाने की मशीन बना देती है।

स. वंचितों और श्रम के प्रति अटूट प्रतिबद्धता (Dignity of Labour) : मार्क्स का पूरा दर्शन 'सर्वहारा' (Proletariat) यानी मजदूर वर्ग की मुक्ति का घोषणापत्र है। मार्क्स श्रम को मनुष्य की चेतना की रचनात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक इसी प्रकार, गांधी जी ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को 'दरिद्रनारायण' (दरिद्र में ही नारायण का वास) कहा। गांधी जी का 'ब्रेड लेबर' (Bread Labour - शारीरिक श्रम का सिद्धांत) का विचार रूस के दार्शनिक टॉल्स्टॉय और बोंदारेव से प्रेरित था, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने भोजन के लिए न्यूनतम शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। यह मार्क्स के श्रम-मूल्य सिद्धांत के बेहद करीब है।

2. वैचारिक असमानताएं (Points of Divergence) : जहाँ गांधी और मार्क्स के 'साध्य' (Ends) यानी अंतिम लक्ष्य में समानता दिखाई देती है, वहीं उस साध्य तक पहुँचने के 'साधन' (Means) और दार्शनिक आधार पूरी तरह से विपरीत ध्रुवों पर खड़े नजर आते हैं। इन असमानताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से गहराई से समझा जा सकता है:

अ. आध्यात्मिक बनाम भौतिकवादी दार्शनिक आधार

- **कार्ल मार्क्स:** मार्क्स का दर्शन **'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद' (Dialectical Materialism)** पर आधारित है। उनके अनुसार, सृष्टि का मूल तत्व 'पदार्थ' या 'भौतिक परिस्थितियाँ' (Economic Factors) हैं। धर्म, ईश्वर और आध्यात्मिकता को मार्क्स "जनता के लिए अफीम" (Opium of the people) मानते थे, जो शोषित वर्ग को भाग्यवादी बनाकर क्रांति से विमुख करती है (Marx, 1844)।
- **महात्मा गांधी:** गांधी जी का पूरा जीवन और दर्शन **अध्यात्म, धर्म और ईश्वर** पर टिका था। उनके लिए 'सत्य ही ईश्वर है' और राजनीति या अर्थशास्त्र को धर्म (नैतिकता) से अलग करना आत्मघाती है। गांधी जी आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए मनुष्य की अंतरात्मा और नैतिक चेतना को जागृत करने पर बल देते हैं।

ब. साधन बनाम साध्य की बहस (Means vs Ends) : यह दोनों विचारकों के बीच का सबसे केंद्रीय और निर्णायक अंतर्विरोध है:

- **मार्क्सवादी दृष्टिकोण:** मार्क्स के लिए 'साध्य' (शोषण की मुक्ति) सबसे महत्वपूर्ण है। यदि साध्य न्यायपूर्ण है, तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन (चाहे वे हिंसक या दमनकारी ही क्यों न हों) वैध हो जाते हैं। मार्क्स का मानना था कि क्रांति इतिहास की दाई (midwife) है और पुराना बीमार समाज बिना हिंसक क्रांति के नए न्यायपूर्ण समाज को जन्म नहीं दे सकता (Marx, 1867)।
- **गांधीवादी दृष्टिकोण:** गांधी जी साध्य और साधन की अपरिवर्तनीय पवित्रता पर अडिग थे। उनका प्रसिद्ध कथन था कि यदि हम बबूल का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ नहीं उग सकता। हिंसक साधनों से कभी भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा अंततः नए शोषकों को जन्म देती है (Gandhi, 1909)।

स. वर्ग-संघर्ष बनाम वर्ग-समन्वय (Class Struggle vs Class Harmony)

- **मार्क्स:** मार्क्स के अनुसार, शोषक और शोषित वर्ग के हित आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। इसलिए इन दोनों के बीच **'वर्ग-संघर्ष' (Class Struggle)** अनिवार्य और अपरिहार्य है। आर्थिक न्याय केवल सर्वहारा द्वारा बुर्जुआ वर्ग को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने से ही आएगा।
- **गांधी:** गांधी जी वर्ग-संघर्ष के स्थान पर **'वर्ग-समन्वय' (Class Harmony) और हृदय-परिवर्तन** के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पूंजीपति भी इंसान हैं और नैतिक सत्याग्रह के माध्यम से उनका हृदय-परिवर्तन किया जा सकता है। इसी सोच से उनका **'ट्रस्टीशिप' (न्यासधारिता)** का सिद्धांत निकला, जहाँ अमीर अपनी मर्जी से गरीबों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति का न्यासी बनता है।

द. केंद्रीयकरण (बड़े उद्योग) बनाम विकेंद्रीकरण (ग्रामोद्योग)

- **मार्क्स:** मार्क्स बड़े उद्योगों, आधुनिक मशीनों और तकनीकी विकास के विरोधी नहीं थे। वे केवल मशीनों के 'स्वामित्व' (Ownership) के विरोधी थे। वे चाहते थे कि बड़े उद्योगों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण न होकर पूरे समाज का नियंत्रण हो।
- **गांधी:** गांधी जी उत्पादन के इस भारी केंद्रीयकरण के ही मूल विरोधी थे। उनका मानना था कि बड़े उद्योग चाहे राज्य के नियंत्रण में हों या निजी हाथों में, वे अनिवार्य रूप से मानवीय स्वतंत्रता का हनन करेंगे और बेरोजगारी बढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने **'आर्थिक विकेंद्रीकरण'** और कुटीर ग्रामोद्योगों (ग्राम स्वराज) पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का प्रतिमान दिया।

3. तुलनात्मक तालिका (Comparative Matrix) : दोनों दार्शनिकों के विचारों के तीव्र विरोधाभास और सूक्ष्म साम्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए नीचे दी गई तालिका एक त्वरित और व्यापक अकादमिक संदर्भ प्रस्तुत करती है:

तुलना का आधार	महात्मा गांधी का प्रतिमान	कार्ल मार्क्स का प्रतिमान
मूल वैचारिक दर्शन	नैतिक, आध्यात्मिक और आदर्शवादी (Spiritual Idealism)	वैज्ञानिक, भौतिकवादी और यथार्थवादी (Scientific Materialism)
सृष्टि/इतिहास का चालक	नैतिक चेतना, आत्मबल और सत्य की शक्ति	आर्थिक संबंध, उत्पादन के साधन और वर्ग-हित
परिवर्तन की पद्धति	अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग और हृदय-परिवर्तन	वर्ग-संघर्ष, सर्वहारा की लामबंदी और सशस्त्र क्रांति

तुलना का आधार	महात्मा गांधी का प्रतिमान	कार्ल मार्क्स का प्रतिमान
निजी संपत्ति पर रुख	निजी संपत्ति का नैतिक नियमन (ट्रस्टीशिप/न्यासधारिता)	निजी संपत्ति का बलपूर्वक पूर्ण उन्मूलन (Abolition)
औद्योगिकीकरण और तकनीक	श्रम-प्रधान तकनीक, कुटीर उद्योग, 'ग्राम स्वराज'	पूंजी-प्रधान तकनीक, बड़े पैमाने पर उत्पादन, सामाजिक स्वामित्व
धर्म और ईश्वर की स्थिति	दर्शन का मूल केंद्र; राजनीति और अर्थशास्त्र का आधार	"जनता की अफीम"; शासक वर्ग द्वारा शोषण का एक उपकरण
अंतिम सामाजिक संरचना	रामराज्य / विकेंद्रीकृत अहिंसक समाज	साम्यवाद / वर्गविहीन, राज्यविहीन औद्योगिक समाज

आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता (Contemporary Relevance) : इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक (दशकों पुराना नव-उदारवादी वैश्वीकरण का दौर) तकनीकी रूप से जितना उन्नत है, सामाजिक-आर्थिक रूप से उतना ही विषम और संकटग्रस्त है। आज जब हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI), चौथी औद्योगिक क्रांति (Fourth Industrial Revolution) और कॉरपोरेट एकाधिकार के युग में जी रहे हैं, तब महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचार केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रह जाते। बल्कि, समकालीन वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में इन दोनों विचारकों की प्रासंगिकता और अधिक प्रखर होकर उभरी है।

आधुनिक समाज की ज्वलंत समस्याओं के आलोक में दोनों विचारकों की प्रासंगिकता का विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है:

1. बढ़ती वैश्विक आर्थिक असमानता और मार्क्सवादी विश्लेषण : वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स का 'अतिरिक्त मूल्य' और 'पूंजी के संकेंद्रण' का सिद्धांत पूरी तरह सटीक बैठता है। आज कॉरपोरेट पूंजीवाद (Corporate Capitalism) ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को इस कदर बढ़ा दिया है कि यह सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है।

- **ऑक्सफैम और पिकेटी के आंकड़े:** थॉमस पिकेटी की कालजयी पुस्तक *'कैपिटल इन द ट्वेन्टी-फर्स्ट सेंचुरी'* (2014) और ऑक्सफैम (Oxfam) की वार्षिक रिपोर्टें लगातार यह चेतावनी दे रही हैं कि दुनिया की 1% आबादी के पास शेष 99% आबादी से अधिक धन है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक *'दास कैपिटल'* (1867) में ठीक इसी परिस्थिति की भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद अंततः धन को कुछ गिने-चुने हाथों में समेट देगा (Piketty, 2014)।
- **डिजिटल सर्वहारा और अलगाव (The Gig Economy):** आज का 'गिग वर्कर' (जैसे जोमैटो, स्विगी, उबर के डिलीवरी पार्टनर्स या फ्रीलांसर) आधुनिक युग का 'डिजिटल सर्वहारा' है। दिखने में स्वतंत्र लगने वाले इस वर्ग के पास न तो सामाजिक सुरक्षा है और न ही काम के निश्चित घंटे। वह मार्क्स द्वारा बताए गए **'श्रम से अलगाव' (Alienation)** का साक्षात उदाहरण है, जहाँ मशीन (एल्गोरिदम) इंसान को नियंत्रित कर रही है।

2. सतत विकास, पर्यावरण संकट और गांधीवादी दर्शन : जहाँ मार्क्स आर्थिक असमानता का सटीक ढांचागत विश्लेषण देते हैं, वहीं महात्मा गांधी आज के सबसे बड़े वैश्विक संकट—**जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और पर्यावरण विनाश**—का सबसे व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान प्रस्तुत करते हैं।

- **सीमित उपभोग बनाम उपभोक्तावाद:** गांधी जी का यह कथन आज के पर्यावरणविदों का मूल मंत्र बन चुका है: *"धरती के पास हर इंसान की जरूरत (Need) को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी एक*

इंसान के लालच (Greed) को पूरा करने के लिए नहीं।" आज की उपभोक्तावादी संस्कृति (Consumerism) ने प्रकृति का जो दोहन किया है, उसकी काट गांधी के 'अपरिग्रह' (Non-possession) और न्यूनतम उपभोग (Minimalism) के सिद्धांत में ही है।

- **कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और ट्रस्टीशिप:** वर्तमान कॉरपोरेट जगत में प्रचलित 'सीएसआर' (CSR) का विचार अनिवार्य रूप से गांधी जी के **'ट्रस्टीशिप' (Trusteeship)** के सिद्धांत का ही एक कानूनी और आंशिक रूप है। आज कंपनियां यह मान रही हैं कि उन्हें अपने लाभ का एक हिस्सा समाज के कल्याण पर खर्च करना ही होगा, क्योंकि उनके पास मौजूद संसाधन समाज की धरोहर हैं।
- **स्थानीयता और सतत विकास (Vocal for Local):** वर्तमान में भारत सरकार और वैश्विक स्तर पर 'आत्मनिर्भरता' और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जो बात की जा रही है, वह मूलतः गांधी जी के **'ग्राम स्वराज' व 'स्वदेशी'** के मॉडल का ही आधुनिक रूपांतरण है। यह मॉडल बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक है।

3. दोनों दृष्टिकोणों की समकालीन प्रासंगिकता का तुलनात्मक ढांचा : आज के आधुनिक संकटों के समाधान में दोनों विचारक किस प्रकार अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, इसे नीचे दिए गए तुलनात्मक प्रतिमान से समझा जा सकता है:

4. एक हाइब्रिड मॉडल की आवश्यकता: 'गांधीवादी मार्क्सवाद' की प्रासंगिकता : आज का समकालीन विश्व न तो मार्क्स की पूर्ण हिंसक क्रांति को स्वीकार करने की स्थिति में है (क्योंकि इतिहास गवाह है कि सोवियत संघ और चीन में मार्क्सवाद के नाम पर राज्य की तानाशाही ने मानवीय स्वतंत्रता को कुचल दिया), और न ही विशुद्ध पूंजीवाद को झेलने की स्थिति में है। इसलिए, आज के 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) में दोनों के विचारों के समन्वय की तीव्र आवश्यकता है।

प्रख्यात भारतीय समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने इसी 'वैचारिक हाइब्रिड मॉडल' की वकालत की थी। आज के संदर्भ में न्याय की स्थापना के लिए हमें:

1. **आर्थिक विश्लेषण मार्क्स का** अपनाना होगा—ताकि हम पूंजीपतियों के एकाधिकार और श्रम के शोषण को पहचान सकें और उस पर कानूनी नियंत्रण (जैसे प्रगतिशील कराधान, श्रम कानून) लगा सकें।
2. **परिवर्तन के साधन गांधी के** अपनाने होंगे—अर्थात सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना लोकतांत्रिक, संवैधानिक, अहिंसक और नैतिक तरीकों से ही की जानी चाहिए, न कि बंदूक की नोक पर।

संक्षेप में कहें तो, कार्ल मार्क्स हमें सामाजिक-आर्थिक असमानता के विरुद्ध 'जागृति और संघर्ष' की चेतना देते हैं, तो महात्मा गांधी हमें उस संघर्ष को 'मानवीय, अहिंसक और स्थाई' बनाए रखने का मार्ग दिखाते हैं।

निष्कर्ष : महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के सामाजिक-आर्थिक न्याय संबंधी दृष्टिकोणों का यह गहन तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट करता है कि दोनों दार्शनिक मूलतः मानवता के इतिहास के ऐसे दो मार्गदर्शक हैं, जिनका अंतिम गंतव्य एक ही था। दोनों ही चिंतक एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था के निर्माण के प्रति पूरी तरह समर्पित थे जो मानवीय गरिमा को सर्वोपरि माने, जहाँ शोषक और शोषित का भेद समाप्त हो और समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले।

इस शोध के आधार पर प्राप्त मुख्य निष्कर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है:

1. शोध के मुख्य निष्कर्ष

- **साध्य की एकता (Unity of Ends):** गांधी और मार्क्स दोनों ही पूंजीवाद जनित विषमताओं, इंसानों के वस्तुकरण और आर्थिक संकेंद्रण के प्रखर विरोधी थे। मार्क्स का 'साम्यवाद' (वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज) और गांधी का 'रामराज्य' (विकेंद्रीकृत, अहिंसक व समतामूलक समाज) वैचारिक स्तर पर एक ही परम लक्ष्य—"शोषणमुक्त समाज"—की ओर संकेत करते हैं।
- **साधनों का मौलिक अंतर्विरोध (Divergence of Means):** दोनों के बीच का सबसे बड़ा और निर्णायक विभाजन साधनों की पवित्रता को लेकर है। मार्क्स जहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतिहास की गतिकी में 'वर्ग-संघर्ष' और 'सशस्त्र क्रांति' को अपरिहार्य मानते हैं, वहीं गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि अपवित्र साधनों (हिंसा) से कभी भी पवित्र साध्य (न्याय) की प्राप्ति नहीं की जा सकती। गांधी जी ने 'हृदय-परिवर्तन' और 'सत्याग्रह' के माध्यम से वर्ग-समन्वय का अधिक मानवीय मार्ग चुना।
- **दार्शनिक अधिष्ठान का अंतर:** मार्क्स का दर्शन 'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद' पर आधारित वैज्ञानिक यथार्थवाद है, जो आर्थिक परिस्थितियों को समाज का नियंता मानता है। इसके विपरीत, गांधी का दर्शन आध्यात्मिक आदर्शवाद पर आधारित है, जो मनुष्य की नैतिक चेतना और आत्मबल को परिवर्तन का मुख्य कारक स्वीकार करता है।

2. समकालीन विश्व के लिए मार्ग: वैचारिक समन्वय : इक्कीसवीं सदी के वर्तमान नव-उदारवादी और कॉरपोरेट पूंजीवादी दौर में, जहाँ एक ओर अमीर-गरीब की खाई (आर्थिक असमानता) चौड़ी हो रही है और दूसरी ओर बेलगाम उपभोक्तावाद के कारण पर्यावरण संकट गहरा रहा है, वहाँ इन दोनों विचारकों में से किसी एक को पूरी तरह छोड़ देना आत्मघाती होगा।

आज के समाज को मार्क्स के 'आर्थिक व ढांचागत विश्लेषण' की आवश्यकता है ताकि पूंजी के संकेंद्रण और डिजिटल सर्वहारा के शोषण को समझा जा सके। किंतु, इस असमानता को दूर करने के लिए हमें मार्ग महात्मा गांधी का ही चुनना होगा। सोवियत संघ और बीसवीं सदी के अन्य देशों में मार्क्सवाद के हिंसक प्रयोगों की परिणति राज्य की क्रूर तानाशाही के रूप में हुई, जो यह सिद्ध करती है कि गांधी जी की 'साधनों की पवित्रता' और 'अहिंसा' की चेतावनी कितनी सटीक थी।

अतः यह शोध पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कार्ल मार्क्स जहाँ आधुनिक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की बीमारियों के सबसे बड़े 'निदानकर्ता' (Diagnostician) हैं, वहीं महात्मा गांधी उस बीमारी को दूर करने वाले सबसे सुरक्षित और स्थाई 'चिकित्सक' (Healer) हैं। मार्क्स हमें अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की चेतना और जागृति देते हैं, तो गांधी उस संघर्ष को लोकतांत्रिक, अहिंसक और मानवीय बनाए रखने की पद्धति सिखाते हैं।

आधुनिक विश्व को यदि एक स्थाई, पर्यावरण-अनुकूल और समतामूलक आर्थिक न्याय की स्थापना करनी है, तो उसे मार्क्स के आर्थिक न्याय की तड़प को गांधी के नैतिक और अहिंसक सांचे में ढालना होगा। आर्थिक समृद्धि तब तक सच्ची समृद्धि नहीं बन सकती, जब तक कि वह नैतिक चेतना और मानवीय मूल्यों से अभिसिंचित न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References) :

1. **Foster, J. B. (1999).** Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology. *American Journal of Sociology*, 105(2), pp. 366-405. *लिंक:* https://doi.org/10.1086/210315
2. **Gandhi, M. K. (1909).** *Hind Swaraj or Indian Home Rule*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, pp. 35-42 (On Machinery), pp. 61-68 (On True Civilization).*लिंक:* https://www.mkgandhi.org/ebks/hind_swaraj.pdf

3. **Gandhi, M. K. (1927).** *An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, pp. 221-225 (Part IV, Chapter II: 'Absorbed in Ruskin'). *लिंक:* https://www.mkgandhi.org/ebks/An-Autobiography.pdf
4. **Gandhi, M. K. (1940).** Doctrine of Trusteeship. *Harijan*, Vol. VIII, No. 24 (August 25, 1940), p. 260. *लिंक:* https://www.gandhiashramsevagram.org/harijan-newspaper/harijan-1940.php
5. **Lohia, R. M. (1963).** *Marx, Gandhi and Socialism*. Hyderabad: Navajivan Trust / Rammanohar Lohia Samata Vidyalaya Nyas, pp. 1-18 (Economics after Marx), pp. 320-335 (The Two Extremes). *लिंक:* https://archive.org/details/marxgandhiandsocialism
6. **Marx, K. (1844).** *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Moscow: Progress Publishers (First Published 1932), pp. 67-78 (Strangement/Alienated Labour). *लिंक:* https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Economic-Philosophic-Manuscripts-1844.pdf
7. **Marx, K. (1859).** *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers, pp. 3-5 (Preface: Base and Superstructure Schema). *लिंक:* https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Critique-Political-Economy.pdf
8. **Marx, K. (1867).** *Das Kapital: Critique of Political Economy (Vol. I)*. Moscow: Progress Publishers, pp. 120-135 (The Production of Surplus Value), pp. 501-515 (The General Law of Capitalist Accumulation). *लिंक:* https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf
9. **Marx, K. (1875).** *Critique of the Gotha Programme*. Moscow: Progress Publishers, pp. 12-17 (Section I: On Distribution of Labor and the Phase of Communist Society). *लिंक:* https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm
10. **Marx, K., & Engels, F. (1848).** *The Communist Manifesto*. London: Burghard, pp. 14-22 (Bourgeois and Proletarians), pp. 27-31 (Proletarians and Communists). *लिंक:* https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
11. **Oxfam International. (2022).** *Inequality Kills: The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality*. Oxfam Briefing Paper, pp. 8-15 (The Wealth Concentration Metaphor), pp. 24-30 (Structural Violence of Economic Models). *लिंक:* https://www.oxfam.org/en/research/inequality-kills
12. **Piketty, T. (2014).** *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press, pp. 23-27 (The General Dynamics of Inequality), pp. 345-360 (The Structure of Inequalities). *लिंक:* https://www.hup.harvard.edu/books/9780674430006
13. **Polanyi, K. (1944).** *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. New York: Farrar & Rinehart, pp. 71-80 (The Self-Regulating Market and the Fictitious Commodities: Land, Labor, and Money). *लिंक:* https://archive.org/details/the-great-transformation-by-karl-polanyi

•